



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यालय द्वारा प्रकाशित

---

चिमला, बुधवार, 26 अक्टूबर, 1994/५ कार्तिक, 1916

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

PERSONNEL (A.L.) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th October, 1994

No. 3-1/75-Karmik (N.I-I).—The Governor, Himachal Pradesh, in continuation of this Department's notification of even number dated 24th September, 1994, is pleased to detain Shri B. S. Dehal, District Revenue Officer, Mandi on temporary duty to Kullu during Kullu Dussehra Festival with effect from 14th October, 1994 to 21st October, 1994 in place of Shri S. P. Rolta, Assistant Commissioner to Deputy Commissioner, Mandi.

2. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that the above officer shall be entitled to draw TA and DA as admissible under the rules.

3. The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Code of Criminal Procedure 1973, is also pleased to appoint the aforesaid officer to be the Executive Magistrate with all the powers of an Executive Magistrate under the said Code, to be exercised within the local limits of Kullu Tehsil w.e.f. 14th October, 1994 to 21st October, 1994 subject to the conditions contained in the Himachal Pradesh Government Home Department letter No. Home-B (B) (12)-5/84, dated 4-12-1984 and 28-12-1994.

By order,

Sd/-

Commissioner-cum-Secretary,

सामाजिक प्रशासन विभाग  
(एफ-शाखा)

धर्मसुचनाएँ

भित्ति-2, 9 जून, 1994

खब्द संख्या प्र० ५० छिपो (एफ०) १(ए) ५-२/९०-१.—इस जिलाय की धर्मसुचना गमनालय के बिना १३-६-१९९४ के क्रम को जारी रखते हुए स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड को शाहीन गढ़ी उप-समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को देनिया/यात्रा भत्ता संलग्न गन्दवन्थ के अनुसार देंगे होंगा।

2. यह खब्द मुद्रण शीर्षक 2235—अधिकारी गुरका एवं नियन्त्रण-200 आव्य स्कीम, ०६—हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण निधि से दिया जायेगा (गैर-गोजना)।

3. संदुक्ष विभ/उप-समिति/प्रवर गविन (सामाजिक प्रशासन) इस उप-समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के देनिया/यात्रा भत्ता भुगताने के लिए नियन्त्रक अधिकारी होंगे। इन सदस्यों के उपरोक्त बिल भी सामाजिक प्रशासन एफ-शाखा में बनाये जायेंगे।

4. इस मतलेपर वित्त विभाग ने आगनी सहायता आनोखारिक संख्या ६३१-५०००(सी०)५० (१) १/८९/१ क्रमांक २३-५-१९९४ द्वारा प्राप्त कर रखी है।

अनुसन्धान

(1) पाला भत्ता :

(क) रेल द्वारा यात्रा :

गे-८८ रोक्योप्रथा क्षेत्रे में ५० रुपये वाली गवान यात्रा जाएगा। और वस्तुतः प्रयोग की गई उपयाएँ दोनों वाली गवान यात्रा भावे का हावार होंगी।

(प) वडक ताता याता :

याता की दण्डों में १५% मील दरी, केंद्र और रेल के गाँधी गमनांश न हो, के बीच में, गैर-पार जारी गमन निम्न राइट मील दरी को हास्यारहीन है।—

(i) यथि याता नाम्बिक भाषा के कारण भी गहरी है।  
जैसे लोह वस प्रारंग एस्टीटॉट्स्टान

(ii) मोटर गाहू और कूटर ताता याता की दण्डों में

(c) पहाड़ी लेत ४० प्रति किलो मील  
के लिए।

(d) भमल थोत ४० प्रति किलो मील  
के लिए।

(iii) गुरी देखती या घण्टी तार ताता याता की दण्डों में

(e) पहाड़ी थोत २.५० प्रति किलो मील  
के लिए।

(f) भमल थोत २.०० रुप प्रति किलो मील  
के लिए।

उपर्युक्त के अन्तिम। उन्हें निम्नलिखित से पारम्परा होते वाले दण्डों दिलाई दिलाया जाए। उनकी कुल भनुपरिणाम के लिए और हास्यारहीन रूप से लोगों को याता याता की दण्डों को नामू निरन्धन और गतों और निम्न लोगों को गठनाधीन बैठिया भता मिलेगा।

(2) दैनिक भत्ते :

(३) गैर-पार जारी भद्रस्थ बैठक के प्रत्येक दिन के लिए यातो-मात्राने वरिष्ठेत और प्रथम श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को लागू होने वाले नियन्त्रण और गतों के प्राप्त्याशीन उच्च दर पर दैनिक भत्ता मिलेगा।

(४) बैठक के दिनों के लिए दैनिक भत्ते के अन्तिम। गवाह वोरे पर और निम्न बोड़े/समिति के लायों से सम्बन्ध बहुरोप स्वेच्छा पर विराम के लिए दैनिक भत्ते का हास्यारहीन होता है।

(क) यदि मुख्यालय से भनुपरिणाम ६ घण्टे से प्रधिक न हो

—

(ख) यदि मुख्यालय से भनुपरिणाम ६ घण्टे से प्रधिक परस्तु १२ घण्टे तक न हो।

७० प्रतिशत

(ग) यदि मुख्यालय से भनुपरिणाम १२ घण्टे से प्रधिक है

पूर्ण

(3)-(अ) प्रबल्लण भत्ता :

गैर-पार जारी तदन्त जो उस स्थान, जहाँ बोड़े/समिति की बैठक आयी हुई है का निवासों हो, को यहाँ प्रबल्लण भत्ता पर या वा और दैनिक भत्तों योग्यता १० घण्टों परि दिन हो लेने का हास्यारहीन होगा। इसमें पहले कि वायां बस्तुतः योग्यता दिया जाये। नियन्त्रक परिषकारी (Controlling officer) वाये को भल्लालित बतेगा और दूसरा भी योग्यता दिये जावाया। ताकि भयप्रहृष्ट करके कि भास्तवि, आग वाये की रायि तो तग नहीं थी अपना

मध्याधारान होंगा। याद इस व्यौर से उनका समाधान नहीं होता तो वह अपने विवेत पर प्रवर्त्तन भत्ते की मड़के भाल दरी तक सीरीज़ित कर सकेगा। यदि ऐसा सदस्य अपनी कार वा प्रयोग करता है तो उसे प्रथम श्रेणी के अधिकारी को मौत दूरी भत्ता अनुज्ञेय दर से अधिकतम 10/- रुपये प्रति दिन के प्रनुगार दिया जायेगा।

(4) मदस्य को यात्रा और दैनिक भत्ता उसके द्वारा इस भाष्य का प्रमाण-पत्र पेश करने पर दिया जायेगा फिर उसने उसी यात्रा के लिए गरकार के लिए अन्य स्वतंत्र से यात्रा या दैनिक भत्ता नहीं लिया है।

(5) गैर-गरकारी मदस्य बोड़ी/मरिति की बैठक से सम्बन्ध की मई वास्तविक यात्रा के लिए और उपर्युक्त स्थाई निवास स्थान जो पहले में ही नामित किया गया हो यात्रा भत्ते का पात्र होगा। यदि कोई सदस्य बोड़ी/मरिति की बैठक में हाजिर होते के लिए अपने स्थाई निवास स्थान से भिन्न अन्य स्थान पर यात्रा करता या बैठक मासान्त त्रोन के पावात उसके स्थाई निवास स्थान से भिन्न प्रत्य स्थान या ऐसे प्रत्य स्थान और बैठक का स्थान जिसकी दूरी कम है को वापिस आता है।

(6) गैर-गरकारी मदस्य को यात्रा भत्ते हे खाने में प्रतिसंलग्नता का क्षण में हिमाचल प्रदेश खजाना नियम के नियम 4.1.7 और 6.1 के उपर्युक्त प्रथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(7) गैर-गरकारी मदस्य जो विद्यान सभा का मदस्य हो, में बोड़ी/मरिति के काम से सम्बन्ध यात्रा की हो, भास्य-ममता पर सांघित विद्यान सभा अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय के बैठक और भत्ते के प्रनुगार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(8) सदस्य उनके समुन्दरण से सम्बन्ध दैनिक भत्ते के लिए हकदार नहीं होता जब विद्यान सभा या विद्यान सभा मरिति जित पर मदस्य गत्र में येतारत है जैसे विद्यान गगा सदस्य को नेतृत्व और भत्ते अधिनियम के अधीन वह अपने दैनिक भत्ते ले रहे हैं, तालाकि यदि वह प्रमाणित करे हि उन्हें भदन के सत्र या विद्यान सभा मरिति के हाजिर होने से निवारित किया गया हो और विद्यान गगा में कोई दैनिक भत्ता नहीं लिया है, वह विनिर्दिष्ट वर सैनिक भत्ते के हकदार होंगे।

(9) मदस्य जिसे विद्यान सभा से अनाहत किया गया हो प्रवर्त्तन भत्ते के अन्तर्गत यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता भी नहीं लेगा।

हस्ताक्षरित/-

आपूर्व एवं भवित्व।

(अनुभाग-क)

गिमला-2, 11 अक्टूबर, 1994.

मंज्या जी ए० ई००८(वी) ८-२/९३.—इस विभाग की गम्भीरता अधिसूचना, दिनांक १०-९-१४ के पैरा ३.११ के त्रम म गिमला नगर नियम मीमा क भीतर आने वाले सभी सरकारी कार्यालय, निवासालय, बोड़ी/नियम तथा शिशा संस्थाओं में दो निम्ननिवित स्थानीय अवकाश प्राप्ति करने का निर्णय लिया गया है:-

1. महा नवमी १२ अक्टूबर, 1994 बृहवार
2. भैया दूज ५ नवम्बर, 1994 शनिवार

आदेशान सार,

आर० के० अनन्द,  
मदस्य मरिति।

## भाषा एवं संस्कृति विभाग

## अधिग्रन्थना

शिगता-2, 7 सितम्बर, 1994

संघर्ष आषा-मी (10)-8/92.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, प्राचीन बोड मठ नाबो गोम्पा को वर्ष 1996 में 1000वीं जयंती मनाई जानी है। जिसके मनाने एवं उचित एवं उठाने हेतु उच्च अंतर्राष्ट्रीय संकालन समिति (स्टीयरिंग कमेटी) के गठन को महार्षि स्वीकृति प्रदान करते हैं। जिसमें निम्नरिक्षित वरदस्य मनोनीत हिस्साते हैं :

संख्या	मन्त्री	अधिकारी
1.	मुख्य मन्त्री	उपायकारी
2.	शिशा मन्त्री	उपायकारी
3.	प्रभारी मन्त्री पर्यटन	उपायकारी
4.	ग्रान्तीश विधायक (श्री कृच्छ्रा राय)	"
5.	श्री गढ़वाल नागरिक, अध्यक्ष द्वारा समिति, काला	"
6.	श्री भगत राष, प्रधान, ग्राम पंचायत, नाबो	"
7.	श्री जीतमेंद्र तन्जीब दोजे, मुख्य लामा पिन मोनिस्टी, स्थिति	"
8.	मुख्य लामा अत्यन्त मोनिस्टी, स्थिति	"
9.	मुख्य लामा तंगमूल मोनिस्टी, काजा सिपाही	"
10.	लामा जोषा प्रभारी कालाकरा समेती जिस्या लाहोल।	"
11.	श्री लोचन दूला, प्रधान लामा महायाग धीढ़ विहार, का, डॉ. शंकर काजा	"
12.	श्री सद्योग दूलकु, लाबो मोनिस्टी	"
13.	प्राचार्य संस्कृत एवं स्टोरी पाठशाला, केलंग	"
14.	श्री पौरिशंकर द्वार्जे (परिदृष्ट बोड दर्शन) मेवानियूत ए. ०५०० प्रार० ०५००, केलंग	"
15.	महानिदिशक पृगतन्त्र मन्त्रेक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली अथवा उनके प्रतिनिधि	"
16.	मुख्य मन्त्रिव	"
17.	मन्त्रिव, लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश	"
18.	मन्त्रिव, जनजातीय विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश	"
19.	मन्त्रिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश	"
20.	मन्त्रिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार	"
21.	सचिव (स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार	"
22.	सचिव (भाषा एवं संस्कृति), हिमाचल प्रदेश सरकार	"
23.	सचिव (पर्यटन), हिमाचल प्रदेश सरकार	"
24.	सचिव (लोक सभा), हिमाचल प्रदेश सरकार	"
25.	प्रबन्ध निदेशक, ही. प्र० तथा पर्यवर्तन निगम हिमाचल प्रदेश।	"
26.	प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश पर्यटन किंगम	"
27.	जिलाधीश लाहौल, हिमाचल प्रदेश	"
28.	जिलाधीश किन्नौर, हिमाचल प्रदेश	"
29.	प्रमुख प्रभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	"
30.	प्रमुख प्रभियन्ता, विचारी एवं जन-स्वाम्य	"
31.	निवेशक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश	"
32.	निवेशक लोक सभार्क, हिमाचल प्रदेश	"
33.	निवेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश	"
34.	निवेशक पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश	"
35.	प्रतिरिक्षित विलाधीश काजा, हिमाचल प्रदेश	"

वरदस्य-सचिव

2. उक्त समिति पूँह से तात्रो वो जाने बालै सड़क को पक्का करने, पर्यटकों को खाने-पीने तथा ठहरने की सुविधा प्रदान करने, विभिन्न समाजार पर्वों-पत्रिकाओं में इस ऐतिहासिक पर्व पर विज्ञापन दिए जाने, ठहरने के लिए भराए धर्मशाला, विद्याम गृह के निर्माण करने, पानी और बिजली की उचित व्यवस्था एवं तावों गोम्पा पर विशेष सांदर्भ प्रकाशित किए जाने इत्यादि अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेगी।

3. गैर-सरकारी सदस्य, समिति से सम्बन्धित यात्रा के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता लेने हेतु सलानीत अनुबन्ध के अनुसार हकदार होंगे।

4. सरकारी मदस्यों को समिति से सम्बन्धित यात्रा के लिए सरकार के नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिकी भत्ता दिया जाएगा।

#### ANNEXURE

##### T.A. and D.A. to Non Official Members of the Committee.

###### (1) Travelling allowance:

(i) *Journey by Rail.*—They will be treated at per with Govt. servants of the first grade, and will be entitled to actual rail fare of the class of accommodation actually used but not exceeding the fare in which the Government servants of the first grade are normally entitled, i.e. accommodation of the highest class by whatever name it may be called provided in the railway by which the journey is performed.

(ii) *Journey By Road.*—They will be entitled to actual fare for travelling by taking single seat in a public bus, and if the journey is performed by motor cycle/scooter, mileage allowance at 60 paise per km, for plain areas and 80 paise per km, in hilly areas, or if journey is performed by full taxi/own car, the Member will be entitled to mileage allowance at Rs. 2.00 per km, in respect of journeys in the plains and Rs. 2.50 per km; in the hills.

(iii) In addition to the actual fare of mileage as per item (i) and (ii) above, a member shall draw daily allowance for the entire absence from his permanent place of residence beginning with departure from the place and ending with return to that place, at the same rate subject to the same terms and conditions as apply to Grade-I officers of the State Government.

###### (2) Daily allowance:

(i) Non-official members will be entitled to draw daily allowance for each day of the meeting at the highest rates as admissible to a Government servant of the first grade for the respective locality.

(ii) In addition to daily allowance for the day(s) of the meeting, a member shall also be entitled to daily allowance for halt on tour and out-station in connection with the affairs of the Committee as under :

- (a) If the absence from headquarters does not exceed 6 hours,

Nil

(b) If the absence from headquarters exceed 6 hours but does not exceed 12 hours.	70%
(c) If the absence from Headquarters exceed 12 hours.	Full

3. *Conveyance allowance.*—Member, resident at a place where the meeting of the Committee is held will not be entitled to travelling and daily allowance on the scale indicated above, but will be allowed only the actual cost of conveyance hire, subject to a maximum of Rs. 10.00 per day. Before the claim is actually paid for, the controlling officer should verify the claim and satisfy himself after obtaining such details as may be considered necessary, that the actual expenditure was not less than the amount claimed.

If such a member uses his own car, he will be granted mileage allowance at the rate admissible to officers of the first grade subject to a maximum of Rs. 10.00 per day.

4. The members will be eligible for travelling allowance for the journey actually performed in connection with the meetings of the committee, from and to the places of their permanent residence to attend the meeting of the committee or return to the place other than the place of his permanent residence after the termination of the meeting. Travelling allowance shall be worked out on the basis of the distance actually travelled or the distance between the place of permanent residence at the venue of the meeting whichever is less.

5. *Members of the parliament.*—The members of the Parliament on the Advisory Committee in respect of journey performed by him by rail, road, air and steamer, in connection with the work of Committee, shall be entitled to TA/DA on the same scale as is admissible to him under 'Salaries and Allowances of Members of Parliament' as amended from time to time.

6. *Members of Vidhan Sabha.*—The non-official members who are members of the Vidhan Sabha shall be entitled to TA/DA in respect of journeys performed in connection with the work of the Committee on the scale as the admissible to them under the Salaries and Allowances of Member of Legislative Assembly.

7. The members will not be entitled to daily allowances in connection with their assignment when the Vidhan Sabha or the Vidhan Sabha Committee on which the members are serving is in session as they will be drawing their daily allowances under the Salaries and allowances of Members of the Legislative Assembly (HP) Act, 1971, from the Vidhan Sabha. However, if they certify that they were prevented from attending the session of the House or the Vidhan Sabha Committee and did not draw any daily allowance from Vidhan Sabha they would be entitled to daily allowance from Vidhan Sabha they would be entitled to daily allowances at the rates as prescribed;

Provided that claims on account of traveling, halting and incidental allowances of Members for attending the meetings of Committees appointed by the Government shall be paid after these have been countersigned by the Secretary Vidhan Sabha, for encashment.

8. The provision of rules 4.17 and 6.1. of the Himachal Pradesh Treasury Rules will apply mutatis in the case of overpayment made on account of travelling allowance to non-official members.

9. The member will also not draw T.A. and D.A. including conveyance allowance which will disqualify them from the Vidhan Sabha.

## 10. Official Members :

The official Members shall be entitled to the travelling and daily allowance admissible to them according to the rules governing them.

ग्रामेण द्वारा,

विनोद लाल,  
आमुनत एवं सचिव।

थम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 सितम्बर, 1994

महावा थम(ए) 4-27/93.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित अनुचित नियोजनों में अकुशल कर्मकारों की न्यूनतम भजदूरी 24 रुपये से 26 रुपये प्रतिदिन या 720 रुपये से 780 रुपये प्रतिमाह पुनरीक्षित कर दी जाएः—

1. कृषि ।
2. सड़कों का निर्माण या अनुरक्षण और भवन किया ।
3. पत्थर तुड़ाई या पत्थर क्रिंशन ।
4. पटिलक मोटर ट्रास्पोर्ट ।
5. घने एवं काले क्रिया ।
6. दुकानें तथा वाणिज्य स्थापन ।
7. रसायन तथा रसायनिक उत्पाद ।
8. इंजिनियरिंग उद्योग ।
9. खाद्य एवं पेय ।
10. शाल बूनाई और गलीचा बनाना ।
11. कपड़ा एवं होजरी उद्योग ।
12. कागज उत्पाद ।
13. ईट भट्ठा उद्योग ।
14. लकड़ी पर आधारित तथा कर्मचर उद्योग ।
15. चाय बागान ।
16. कारखाना अधिनियम, 1948 की आरा 2 (के) में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया ।
17. भद्र निर्माण शालाओं शराब कारखानों और अन्य अनुसंधान प्रबालनों जैसे बोतलें भरने ।
18. सीमेट कारखानों तथा सीगेट से बनने वाले अन्य उत्पाद ।
19. आरा भणीने ।
20. निजी ईक्षणिक संस्थान ।
21. कास्टिंग उद्योग ।
22. चमड़ा उद्योग ।
23. इलेक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्रीज ।
24. होटल/रेस्त्रां ।

2. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि उक्त वर्णित अनुसृचित नियोजनों के बारे में धर्ध-कुशल, कुशल और छव्य-कुशल भजदूरों की न्यूनतम भजदूरी की दर 8.33 प्रतिशत बढ़ा दी जाएँ, परन्तु यह 2 रुपये प्रतिदिन में कम नहीं है ।

3. हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि जो कर्मकार अनाजातीय क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों

में कुपि, सड़कों का निर्माण और अनुरक्षण वालिकी तथा काठ, पत्थर काँड़िग और पत्थर तुड़ान के अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत कर्मजारों को क्रमशः 25 प्रतिशत और 12/1-2 प्रतिशत की प्रस्तावित पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दरों के अतिरिक्त और बढ़ोतरी की जायेगी। जो मजदूर सुरंगों में कार्यरत है, उन्हें पिछले बर्पी की तरह और 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी और इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों व पिछड़े क्षेत्रों में मजदूरी क्रमशः 25 प्रतिशत तथा 12/1-2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जायेगी।

4. अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1947 का 5) का धारा 5 के अनुसरण में इस प्रस्ताव को उन व्यक्तियों की मूचना के लिए प्रकाशित करते हैं जिनकी उक्त प्रस्ताव से प्रभावित होने की सम्भावना है, उक्त प्रस्ताव पर कोई आवधि या सुवाद ही तो उसे धमायक्त, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 को इसके राज्यपत्र हिमाचल प्रदेश (श्रावण) में प्रकाशित होने की तारीख से दो महीनों की अवधि के अवसान से पहले विवार के लिए भेजे।

5. प्रस्तावित पुनरीक्षित दरें 1-10-94 से लागू होंगी।

प्रादेश द्वारा,

एस० एस० सिद्धू,  
वितायकत एवं सचिव।

[Authoritative english text of this Department's notification No. Shram (A)4-27/93 dated 30-9-94, as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

## LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th September, 1994

No. Shram (A)4-27/93.—Whereas it appears to the Governor of Himachal Pradesh that the Minimum rates of wages of un-skilled workers should be revised from Rs. 24 to Rs. 26 per day or Rs. 720 to Rs. 780 per month in respect of the under mentioned scheduled employments :—

1. Agriculture.
2. Construction or maintenance of roads and in building operation.
3. Stone breaking or in stone crushing.
4. Public Motor Transport.
5. Forestry and Timbering operation.
6. Shops and Commercial Establishments.
7. Chemical and Chemical Products.
8. Engineering Industries.
9. Food and Drinks.
10. Shawl Weaving and Carpet Making.
11. Textile and Hosiery Industries.
12. Paper products.
13. Brick Kiln Industries.
14. Wood based and Furniture Industries.
15. Tea Plantations.
16. Manufacturing Processing as defined in section 2 (k) of Factory Act, 1948.
17. Breweries Distilleries and other incidental operation like bottling.
18. Cement Factory and manufacturing of other cement products.

19. Saw Mills.
20. Private Educational Institutions.
21. Casting Industries.
22. Leather Industries.
23. Electronic Industries.
24. Hotels/Restaurants.

2. Whereas it appears to the Governor of Himachal Pradesh that the minimum rates of wages of semi-skilled, skilled and highly-skilled workers should be increased by 8.33% subject to the minimum of Rs. 2 per day in respect of the above mentioned scheduled employments.

3. Whereas it appears to the Governor of Himachal Pradesh that the minimum wages of the workers working in the Tribal Areas and Backward areas engaged in the scheduled Employments of agriculture, construction and maintenance of roads, forestry and timbering, stone crushing and stone breaking should further be enhanced by 25% and 12½% respectively over and above the proposed revised minimum rates of wages. For workers working in the tunneling operation, the proposed increase in minimum wages will be further enhanced by 20% as in the past years, and in addition there will be an increase of 25% and 12½% in wages for Tribal and Backward areas respectively.

4. Now, therefore, in pursuance of section-5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish this proposal for the information of the persons likely to be affected thereby. Any objections/suggestions on the above proposal may be sent to the Labour Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla-I for consideration before the expiry of 2 months from the date of its publication in the Himachal Pradesh Rajpatra.

5. The proposed revised rates will be applicable w. e. f. 1-10-94.

By order,

S. S. SIDHU,  
Financial Commissioner-cum-Secretary.

लोक मरम्पकं विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 6 अक्टूबर, 1994

संख्या पत्र-ए(4)2/85-1.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, विकासात्मक पत्रान्विति के लिए पत्रामारों को सम्मान देने के लिये वर्ष 1993 के तिये इस विभाग की अधिसूचना संख्या पत्र-ए(4)-2/85-1, दिनांक 2-5-1994 द्वारा गठित छातवीन ममिति में थी औपचारिक बातचीजों, स्थानीय सम्पादक, जनसता, चण्डीगढ़ के स्थान पर श्री विजय सुड्गन, समादान, दैनिक ट्रिव्यून, चण्डीगढ़ को गदस्य मनोनीत करन की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,

जे ० पी० नेगी,  
ग्राम्यकल एवं गवित ।

[Authoritative English Text of this Government Notification Number Rev. 2E (3) 17/93, dated 26-9-1994, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

## REVENUE DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th September, 1994

No. Rev. 2E (3) 17/93.—Whereas Shri Roop Singh Thakur, (Retired Judge of Himachal Pradesh High Court) has been appointed Arbitrator to give award within a period of 4 months *vide* notification of even number, dated 8/11-11-1993.

2. And whereas the said Arbitrator has not been able to give the award within the stipulated period.

3. Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 9 of the Himachal Pradesh Requisition of Immoveable Property Act, 1987, is pleased to extend the period for making the award upto 9th August, 1994.

By order,

P. T. WANGDI,  
Financial Commissioner-cum-Secretary,

प्रामाणि विभाग तथा पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 27 अक्टूबर, 1994

भख्या यार ० डी० डी०-१-ए (वी) (२)-२/९४—राज्याल, हिमाचल प्रदेश, प्रामाणि विभाग तथा पंचायती राज विभाग में दिनांक २४-८-१९९४ को हुई विभागीय पदोन्नति मिसित की निकाशित पर श्री टेक चन्द शर्मा, अधीक्षक ग्रेड-II, कार्यालय खण्ड विभाग एवं पंचायत अधिकारी गोहर, जिला मण्डी को २२००—४००० के बतनमान में प्रामाण विकास तथा पंचायती राज निदेशालय में अधीक्षक ग्रेड-I (राजपत्रि थ्रेणी-II) के पद पर स्थानापन्न (Officiating) रूप से पदोन्नत करने के सहर्ष प्रादेश देते हैं।

यह पदोन्नति श्री निकाश राम, अधीक्षक ग्रेड-II के विरुद्ध सतर्कता विभाग में चल रहे मामले के अन्तिम निर्णय पर आधारित होती है।

इनकी परिवेश अवधि इनके नार्यग्रहण की तिथि से दो वर्ष होती जिस यथा स्थिति बढ़ाया जा सकता है।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/-  
दृष्टि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव।

शिमला-2, 7 अक्टूबर, 1994

संख्या पी० सी० ए८०-ए८० ए० (५) ३१/९०.—अपेक्षित श्री रजदीप सिंह, प्रधान, प्राम पंचायत औदीशिमान, विभाग खण्ड संघाह, जिला भिरपौर के विरुद्ध पुलिस थाना रेणुकाजी में दिनांक २४-६-१९९३

को प्रशंसा सुनना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी जिसमें आरोप है कि प्राथमिक गाँठाला कोटीधिमान के पुराने भवन को पिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से निया कर उसका नामानुसूद बुद्धि नहीं किया गया;

और क्योंकि याना शाहदात, पुनिस याना रेणु, जो मामले की मांग की स्थानबीत की ओर और श्री रणदीप सिंह, प्रधान का जर्म जेरधारा 3 (2) "ए" प्रीवेन्यून आफ ईंडेज टू पब्लिक प्रोटोर्टी अधिनियम, 1984 का सावित होने पर गिरफ्तार किया गया जो बाद में बर जमानत मुचलवा। पर बाब्रदालत इहां हुआ है और बालान अतिरिक्त मुक्त नामियां दण्डधिकारी की शादीलत में प्रस्तुत निया गया है;

और क्योंकि उत्तरायण गिरमोर से भी इम वारे रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें उन्होंने सुनित किया है कि "प्रशासन जनत के डार" कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त पंचायत के दोरे के समय श्री रणदीप सिंह, प्रधान ने प्राथमिक गाँठाला के भवन के नव निर्माण हेतु राशि मांगी थी तथा वह पुराने भवन को निया कर नया भवन बनवाना भव्यते थे। उन्हें राखिं उपलब्ध करवाने का ग्राएवाभन दिया गया था तथा उसे पुराने भवन को नियाने के लिए सक्षम प्रधिकारी से अनुमति लेने वारे वह गया था;

और क्योंकि श्री रणदीप मिह ने श्री मित सिंह तीमर का नाम ग्राम पंचायत कोटीधिमान के परिवार रजिस्टर भाग 1 से टाट दिया जिसके लिए वह सक्षम नहीं।

प्रा: हिमाचल प्रदेश के राजनीति, उन शिक्षियों के अन्तर्गत जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियनावली, 1971 के नियंत्रण 77 के प्रधीन गठित हैं, श्री रणदीप सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत कोटीधिमान, विलास घण्ड संगड़ाह, जिला भिरमान, को प्रदर्श देते हुए कि वह ग्राम वारों नियमों ने उन्हें उपरोक्त गुरुत्वों के लिए हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायती राज अधिनियम, 1994 का धारा 145 के अन्तर्गत प्रधान पद से नियमित हिता जाए। उनका उत्तर इम ग्राम पंचायती नामियां के जारी होने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर-2 इस नियमालय में पहुँच जाना चाहिए। अन्यथा वह समझा जाएगा कि वह उक्त आरोपों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहते और उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाही की जायेगी।

हस्ताक्षरित/-  
श्रीतिरक्त सचिव ।

## SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 23rd December, 1993*

No. STV (Env.) A (10)-3/93 — The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute the Project Level Environmental Management Committee in respect of Bhaba, Baner, Uhl Stage-II and Kol Dam Projects in Himachal Pradesh under the Chairmanship of the following with immediate effect :—

Sl. No.	Name of the Project	Chairman
1	2	3
1.	Bhaba Project	Chief Engineer, H.P.S.E.B., Incharge of the Project.
2.	Baner Project	Chief Engineer, H.P.S.E.B., Incharge of the Project.
3.	Uhl Stage-II Project	Chief Engineer, H.P.S.E.B., Incharge of the Project.
4.	Kol Dam Project	Chief Engineer, H.P.S.E.B., Incharge of the Project.

*Official Members of each Projects*

1. Conservator of Forests Concerned	.. Member
2. Geologist from the Department of Industries concerned	.. Member
3. Superintending Engineer (IPIU) of area	.. Member
4. Director of Fisheries, Himachal Pradesh	.. Member
5. Deputy Director (Agriculture) in the area	.. Member
6. Rep. of Deputy Commissioner concerned	.. Member
7. Rep. of Secretary (Tourism) to the Government of Himachal Pradesh	.. Member
8. Rep. of Himachal Pradesh State Pollution Control Board	.. Member
9. Superintending Engineer of the Project or the seniormost SEB-Engineer.	.. Member-Secretary.

2. The functions of the committee will include exercising check on cutting of forests and compensatory afforestation, prevention of soil erosion through proper arrangement of slopes; aquatic life and tourism promotion etc.

3. These Committees may meet at - short -suitable intervals at Project level Hqrs. to review the progress made in implementations the safeguards by each Project authority.

4. The Official members of those committees will be entitle to TA/DA admissible under the normal rules applicable to them from their respective departments.

By order,

S. K. SOOD,  
Commissioner-cum-Secretary.